



# दिल्ली राज्यपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/पौष 2, 1934

[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 250

No. 15]

DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/PAUSA 2, 1934

[ N.C.T.D. No. 250

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह ( पुलिस-II ) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

सं. फा. 8/3/2011/गृह-II/468.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14 फरवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या यू-11030/4/88-यूटीएल/का.आ. 125(अ) के साथ पठित भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 17 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की सतरकता जांच यूनिट में कार्यरत पुलिस निरीक्षकों को, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय मामलों पर निरीक्षक स्तर तक के कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संबंध में शिकायतों की जांच के लिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा बारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। इन शक्तियों के प्रत्यायोजन से पुलिस आयुक्त को शिकायत प्राप्त करने तथा इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने संबंधी विवेकाधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
बी. के. तिवारी, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd January, 2013

No. F. 8/3/2011/HP-II/468.—In pursuance of first proviso to Section 17 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11030/4/88-UTL/S.O. 125(E), dated the 14th February, 1989, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize Inspectors of Police, working in the Vigilance Investigation Unit of Delhi Police, to investigate cases on complaints relating to junior police officers up to the level of Inspectors, punishable under the said Act, without the order of a Metropolitan Magistrate and make arrest therefor without a warrant, in the whole of National Capital Territory of Delhi. This delegation of power would, however, not affect the discretion of Commissioner of Police to get a complaint received by him, be investigated by Anti-Corruption Branch, Government of National Capital Territory of Delhi or Central Bureau of Investigation.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
B. K. TIWARI, Dy. Secy. (Home)